न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जेसिंडा अर्डर्न ने इस्तीफा देकर चौंकाया, बोलीं- अब नहीं बची ऊर्जा

वेलिंगटन ।

न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जेसिंडा अर्डर्न ने इस्तीफा देने का एलान कर चौंका दिया। गुरुवार को पार्टी की वार्षिक कॉकस बैठक में जेसिंडा ने कहा कि काम करने के लिए अब ऊर्जा नहीं बची है। अब इस्तीफा देने का समय है। मैं जा रही हूं, क्योंकि इस तरह की खास भूमिका के साथ जिम्मेदारी जुड़ी होती है। यह जानने की जिम्मेदारी कि आप नेतृत्व करने के लिए कब सही व्यक्ति हैं और कब नहीं। मुझे पता है कि इस काम के लिए कितनी मेहनत लगती है। मुझे पता है कि मेरे पास इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए अब पर्याप्त शक्ति नहीं बची है।

7 फरवरी को समाप्त होगा कार्यकाल - प्रधानमंत्री के रूप में जेसिंडा का कार्यकाल 7 फरवरी को समाप्त होगा। उन्होंने कहा, मैं इंसान हूं, राजनेता भी इंसान होते हैं। जब तक हम कर सकते हैं, हम वह सब करते हैं जो हम कर सकते हैं। जेसिंडा ने कहा कि मैंने गर्मियों की छुट्टी के दौरान विचार किया था कि क्या मेरे पास भूमिका में बने रहने की ऊर्जा है या नहीं और निष्कर्ष निकला कि ऊर्जा नहीं थी।

जीवन के सबसे संतोषजनक साढ़े पांच साल - जेसिंडा ने कहा, ये मेरे जीवन के सबसे संतोषजनक साढ़े पांच साल रहे हैं। लेकिन इसकी अपनी चुनौतियां भी हैं- आवास, बाल गरीबी और जलवायु परिवर्तन पर केंद्रित एजेंडा के बीच हमने एक घरेलू आतंकी घटना, एक बड़ी प्राकृतिक आपदा, एक वैश्विक महामारी और एक आर्थिक संकट का सामना किया है। अर्डर्न ने कहा कि उनके पास अपने परिवार के साथ अधिक समय बिताने के अलावा भविष्य की कोई योजना नहीं है। यह पूछे जाने पर कि न्यूजीलैंड के लोग उनके नेतृत्व को कैसे याद रखेंगे, अर्डर्न ने कहा कि एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जो हमेशा दयालु बनने की कोशिश करता है। उन्होंने कहा, मैं इसलिए नहीं जा रही हूं क्योंकि मेरा मानना है कि हम चुनाव नहीं जीत सकते, बल्कि इसलिए कि मुझे विश्वास है कि हम जीत सकते हैं और जीतेंगे और हमें उस चुनौती के लिए नए नेतृत्व की जरूरत है।

वित्त मंत्री ग्रांट रॉबर्टसन दौड़ में सबसे आगे - अर्डर्न की जगह कौन लेगा, यह अभी तक स्पष्ट नहीं है। उप नेता और वित्त मंत्री ग्रांट रॉबर्टसन को इस भूमिका के लिए सबसे आगे माना जाएगा। हालांकि उन्होंने गुरुवार को कहा कि वह इस पद की मांग नहीं करेंगे। एक बयान में उन्होंने कहा कि मैं खुद को लेबर पार्टी के नेतृत्व का उम्मीदवार बनने के लिए आगे नहीं रख रहा हूं। 2017 में जेसिंडा दुनिया की सबसे कम उम्र की महिला प्रधानमंत्री बनी थीं।

न्यूज ब्रीफ

सूखे के चलते बंद हो गई अमेरिकी कस्बे की पानी सप्लाई, अब टॉयलेट साफ करने के लिए भी बारिश के पानी पर निर्भर

वाशिंगटन । एरिजोना इन दिनों सूखे की चपेट में है। पानी बचाने के लिए लोग नए-नए प्रयोग कर रहे हैं। इस बीच यहां के एक शहर स्कॉट्सलेट ने रियो वर्डे की जल आपूर्ति ही रोक दी है, जिससे सैकड़ों परिवार एक जनवरी से पानी की कमी का सामना कर रहे हैं। स्कॉट्सलेट के इस विवादास्पद कदम से आक्रोशित लोगों ने अब न्यायालय का दरवाजा खटखटाया हैं। उधर, स्कॉट्सडेल का कहना है कि वह रियो वर्डे की जल आपूर्ति के लिए जिम्मेदार नहीं है। स्कॉट्सलेट ने कहा है कि वह कई वर्षों से रियो वर्डे को चेतावनी और सलाह देता आ रहा है कि वह सूखे की अवधि के दौरान हमारी आपूर्ति पर निर्भर नहीं रह सकता। रियो वर्डे के करीब 500 से ज्यादा घर ऐसे हैं, जहां पीने का पानी तक उपलब्ध नहीं है। लोग दैनिक कार्यों के लिए नए-नए और कठिन प्रयोग कर रहे हैं। स्थानीय निवासियों का कहना है कि वे टॉयलेट के लिए बारिश के पानी का उपयोग कर रहे हैं तो खाने के लिए पेपर की प्लेट प्रयोग में ला रहे हैं, जिससे पानी बच सके। वहीं एक अन्य निवासी डी थॉमस ने बताया कि वह अपने परिवार की जरूरतों के लिए पूल में इकट्ठा हुए बारिश के पानी को प्रयोग करने के लिए मजबूर है। आम दिनों में वह इसका प्रयोग नहाने के लिए करते हैं। उधर, स्थानीय निवासियों की ओर से इस मामले में मुकदमा दर्ज कराया गया है। मुकदमे में कहा गया है, परिवारों के लिए खुद नहाने या अपने शौचालयों को फ्लश करने के लिए पानी नहीं है। यहां तक की उनके पास पीने का पानी भी नहीं बचा है, जो एक बुनियादी आवश्यकता है। उधर, राज्य के सांसदों द्वारा हाल ही में एक बिल पेश किया गया है।

मास्क न पहनने पर भारतीय मूल की महिला पर हुई थी नस्लीय टिप्पणी, छाती पर मारी गई थी लात

सिंगापुर । सिंगापुर में दो साल पहले भारतीय मूल की महिला पर हुए हमले और नस्लीय टिप्पणी मामले में अदालती सुनवाई हुई। इस दौरान पीड़ित महिला हिंडोचा नीता विष्णुभाई ने सात मई, 2021 को कांग हाउसिंग एस्टेट में हुई घटना का जिक्र किया है। पीड़ित महिला ने बताया है कि आरोपी ने उस पर नस्लीय टिप्पणी की और उसकी छाती पर लात मारी थी। वहीं आरोपी वोंग जिंग फोंग ने खुद पर लगे आरोपों से इनकार किया है। बुधवार को मामले में पहले ट्रायल के दिन पीड़ित हिंडोचा अदालत में पेश हुई। वह आरोपी जिंग फोंग को देखते ही रोने लगी, जिसके बाद न्यायाधीश शैफुद्दीन सरुवन ने मामले को थोड़ी देर के लिए रोक दिया। करीब 30 मिनट बाद सुनवाई फिर से शुरू हुई, जिसके बाद हिंडोचा ने अदालत को बताया कि हमले के बाद वह काफी डरी हुई थी और रो रही थी। हिंडोचा ने बताया कि घटना उस समय की है, जब कोरोना को लेकर सिंगापुर में मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया था। पीड़िता ने बताया कि वह आमतौर पर तेज कदमों से चलती है, ऐसे में सांस लेने के लिए उसने अपना मास्क थोड़ा नीचे कर लिया था।

तिब्बत में एवलांच, 8 की मौतः कई लापता लोगों की तलाश 24 घंटे बाद भी जारी, चीन ने रातोंरात 131 लोगों की टीम भेजी

ल्हासा। तिब्बत में एवलांच की चपेट में आने से 8 लोगों की मौत हो गई । स्टेट मीडिया के मुताबिक हादसा तिब्बत के दक्षिण-पश्चिमी इलाके न्यिंगची शहर में डोक्सोंग ला सुरंग के पास हुआ। चीनी सरकार ने घटनास्थल पर रेस्क्यू टीम भेजी है। ये टीम मृतकों के शवों को बाहर निकाल रही है। साथ ही लापता लोगों की तलाश में जुटी है।मंगलवार रात 8 बजे के करीब हुए हादसे के बाद कई वाहन और लोग डोक्सोंग ला सुरंग के पास फंसे हुए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन के 24 से ज्यादा घंटे बीत चुके हैं। लोकल अधिकारियों ने बताया कि अभी यह पता नहीं लग पाया है कि कितने लोग लापता हैं। घटना की जानकारी मिलते ही 131 लोगों के सुरक्षा दलों और 28 वाहनों को बचाव कार्य के लिए भेजा गया था।

यूएन चीफ ने दी बड़े खतरों की चेतावनी

जेलेंस्की बोले- जंग खत्म करने के लिए पूरी दुनिया के समर्थन की जरूरत

दावोस ।

संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने बुधवार को विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक में वैश्विक हालातों पर चिंता जाहिर की है। इस दौरान उन्होंने इन हालातों से निपटने के तरीकों को लेकर चेतावनी भी दी है। उन्होंने कहा कि दुनिया कई मोर्चों पर बड़े संकटों का सामना कर रही है। इस पर अब तक बहुत कुछ किया भी जा चुका है। इसके अलावा इन बड़े खतरों के नुकसान को नियंत्रित करने और अवसरों का लाभ लेने के लिए सभी को मिलकर काम करना होगा।

दावोस में विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक के दौरान संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने विशेष संबोधन दिया। इसमें उन्होंने जीवाश्म ईंधन के प्रति बढ़ती निर्भरता को कम करने और प्रकृति के खिलाफ किए रहे युद्ध को रोकने का भी आह्वान किया। उन्होंने कहा कि दुनिया पर मंडरा रहे बड़े संकटों से निपटने के लिए कोई सटीक समाधान नहीं होता है, लेकिन हम नुकसान को नियंत्रित करने और अवसरों को हासिल करने के लिए काम कर सकते हैं।

उन्होंने कहा कि अब इस बात की जरूरत पहले से कहीं अधिक है कि हम अपनी खंडित दुनिया में सहयोग के रास्ते तैयार करें। संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने कहा कि मैं यहां उस चुनौती के पैमाने या हमारी दुनिया की दयनीय स्थिति को गले लगाने के लिए नहीं हूं। हम समस्याओं का सामना तब तक नहीं कर सकते जब तक कि हम उन्हें पूरी तरह से आंखों में न देखें। हमारी दुनिया कई मोर्चों पर बड़े खतरों से त्रस्त है। जलवायु परिवर्तन, भूख, संघर्ष, वित्तीय संकट, मानवाधिकारों का उल्लंघन, वैश्विक विभाजन सरीखी कई समस्याएं हैं। दुनिया के कई हिस्से मंदी का सामना कर रहे हैं। बावजूद इसके इन पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है।

अर्थशास्त्रियों ने जताई 2023 में वैश्विक मंदी की आशंका - विश्व आर्थिक मंच के अधिकांश मुख्य अर्थशास्त्रियों ने 2023 में वैश्विक मंदी की आशंका जताई है। उन्होंने अमेरिका और यूरोप में और अधिक मौद्रिक तंगी का भी अनुमान जताया है। विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक में एक रिपोर्ट जारी की गई है। ये

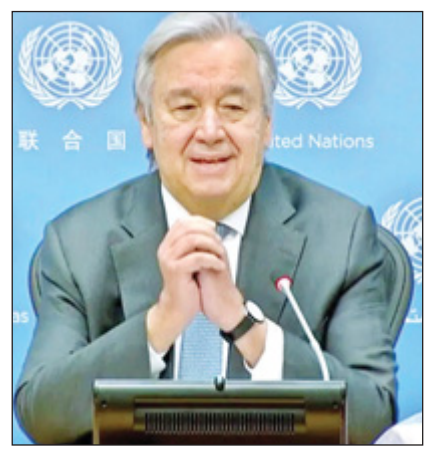

निष्कर्ष डब्ल्यूईएफ की पांच दिवसीय वार्षिक बैठक के दौरान मुख्य अर्थशास्त्री आउटलुक: जनवरी 2023 नाम से जारी एक रिपोर्ट का हिस्सा हैं। लगभग दो-तिहाई मुख्य अर्थशास्त्रियों का मानना है कि 2023 में वैश्विक मंदी आने के आसार है। इनमें से 18 प्रतिशत इसे अत्यंत संभावित मानते हैं। यह सितंबर 2022 में किए गए पिछले सर्वेक्षण की तुलना में दोगुने से भी अधिक है। डब्ल्यूईएफ ने मंगलवार को एक विज्ञप्ति में कहा कि एक तिहाई उत्तरदाताओं का मानना है कि इस साल वैश्विक मंदी की संभावना नहीं है। डब्ल्यूईएफ ने कहा कि एक आम सहमति बनी हुई है कि 2023 में आर्थिक विकास की संभावनाएं धूमिल हैं। इसमें खासकर यूरोप और अमेरिका की स्थिति और खराब होने वाली है।

रूस-यूक्रेन युद्ध दो व्यवस्थाओं के बीच की जंग - यूक्रेनी नोबेल शांति पुरस्कार विजेता ऑलेक्ज़ेंड्रा मत्वीचक ने मानवाधिकारों का उल्लंघन करने वाले देशों के लिए चिंता जताई है। दावोस में बुधवार को विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक 2023 के दौरान लोकतंत्र पर एक सत्र में बोलते हुए उन्होंने कहा कि मानवाधिकारों का उल्लंघन करने वाले देश पूरी दुनिया के लिए खतरा हैं। रूस-यूक्रेन युद्ध का जिक्र करते हुए उन्होंने यह भी कहा कि यूक्रेन में युद्ध सिर्फ दो राज्यों के बीच का युद्ध नहीं है। यह दो व्यवस्थाओं - अधिनायकवाद और लोकतंत्र के बीच युद्ध है।

गौरतलब है कि ऑलेक्ज़ेंड्रा मत्वीचक कीव स्थित एक गैर-लाभकारी संगठन सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज की प्रमुख हैं। उन्हें 2022 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वे उन लोगों के साथ काम करती हैं जो रूसी कैद से बच गए थे।

रूस ने आतंकियों के बीच बनाई जगह - यूक्रेन पर रूस के आक्रमण को लगभग एक साल होने को आया है। इस मौके पर यूक्रेन के राष्ट्रपति वलोडिमिर ज़ेलेंस्की ने बुधवार को विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक के दौरान प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि रूस को युद्ध शुरू करने के लिए कुछ सेकंड चाहिए थे, लेकिन दुनिया ने उसपर प्रतिबंध लगाने में कई दिन लगा दिए। इस दौरान ज़ेलेंस्की ने कहाकि रूस ने आतंकवादियों के बीच एक जगह अर्जित की है। उन्हें अपनी गलतियों को पहचानना चाहिए और उन्हें हमारी क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करना चाहिए।

विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक के दौरान कीव से एक विशेष ऑनलाइन संबोधन में उन्होंने कहा कि जब रूस ने बिना किसी हिचकिचाहट के क्रीमिया पर आक्रमण किया तो दुनिया उस पर प्रतिबंध लगाने में हिचकिचा रही थी। वैश्विक समुदाय से रूस के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए उन्होंने कहा कि दुनिया को अब संकोच नहीं करना चाहिए। दुनिया को रूस की तुलना में तेज़ी से आगे बढ़ना चाहिए।

जेलेंस्की ने कहा कि वह हम नहीं थे जिन्होंने युद्ध शुरू किया था। हालांकि अब हमें ही इस युद्ध को समाप्त करना होगा। इसके लिए पूरी दुनिया को यूक्रेन का समर्थन करने के लिए एकजुट होना होगा। उन्होंने कहा कि इस युद्ध को जीतने और संकट से उबारने के लिए यूक्रेन को सेना के साथ-साथ वित्तीय सहायता की भी जरूरत है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने कहा कि उन्हें अपनी सुरक्षा की चिंता नहीं है, वह कहीं नहीं जाना चाहते हैं और युद्ध लड़ने के लिए उन्हें बस गोला-बारूद की जरूरत है।

अमेरिका के मैरीलैंड में लेफ्टिनेंट गवर्नर बनीं अरुणा मिलर: भगवत गीता पर ली शपथ; पद संभालने वाली पहली इंडियन-अमेरिकन सिटीजन

मैरीलैंड।

भारत में पैदा हुईं अरुणा मिलर ने अमेरिका में इतिहास रच दिया है। वे अमेरिका के मैरीलैंड राज्य की पहली इंडियन-अमेरिकन लेफ्टिनेंट गवर्नर बन गई हैं। उन्होंने भगवत गीता पर हाथ रखकर शपथ ली और पद संभाला। 58 साल की अरुणा का जन्म भारत के हैदराबाद में हुआ था। वे 1972 में अपने परिवार के साथ अमेरिका गई थीं। उन्हें साल 2000 में अमेरिका की नागरिकता मिली थी। अरुणा मैरीलैंड राज्य की 10वीं लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। 2010 से 2018 तक वे मैरीलैंड के हाउस ऑफ डेलीगेट में भी रही थीं। उन्होंने वहां अपने दो कार्यकाल पूरे किए थे। अरुणा भारतीय-अमेरिकी लोगों के बीच काफी लोकप्रिय हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर के चुनाव में कई ट्रंप समर्थकों ने उनका समर्थन किया था।

अरुणा पेशे से कैरियर ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियर हैं। उन्होंने 25 साल तक मैरीलैंड के ट्रांसपोर्टेशन डिपार्टमेंट में काम किया है। उनके पिता भी एक मैकेनिकल इंजीनियर थे और 1960 के दशक में अमेरिका गए थे। 1972 में वे अपनी पत्नी और 3 बच्चों को भी अमेरिका ले गए थे। उस समय अरुणा 7 साल की थीं। अरुणा ने शपथ के बाद स्पीच में सफलता का श्रेय अपने परिवार को दिया। उन्होंने स्पीच में अमेरिका में स्कूल के पहले दिन की घटना का खास जिक्र किया। उन्होंने बताया- कोई भी मेरे जैसा नहीं दिख रहा था। मुझे अंग्रेजी बिल्कुल नहीं आती थी लेकिन मैं सबके साथ फिट होना चाहती थी। इसलिए मैंने सोचा कि जैसा बाकी बच्चे करेंगे, मैं भी ठीक वैसा ही करुंगी। मैंने उस दिन कैंटीन में पहली बार अमेरिकी खाना खाया और ठंडा दूध पीया। पहले मुझे सब ठीक लग रहा था लेकिन क्लास में पहुंचते ही मुझे उल्टी हो गई। इसके बाद मेरी मां मुझे स्कूल से घर ले गईं। मैंने अपनी मां से कहा कि मुझे वापस अपनी दादी के पास भारत जाना है। बड़े होने पर एहसास हुआ कि दूसरों के बनाए स्पेस में मुझे फिट होने की कोई जरूरत नहीं है। जरूरी यह है कि मैं हर जगह जैसी सच में हूं, वैसी ही रहूं। मेरीलैंड में तीन उच्च पदों पर अश्वेत चुने गए हैं। वेस मूरे को गवर्नर चुना गया है, अरुणा लेफ्टिनेंट गवर्नर बनी हैं और एंथनी ब्राउन अर्टानी जनरल बने हैं।

सैन्य और कूटनीति में मिला करारा जवाब, तो जलयुद्ध की तैयारी कर रहा चीन! भारत ने भी कसी कमर

बीजिंग ।

कूटनीति और सैन्य नीति के मोर्चे पर भारत से करारा जवाब मिलने के बाद चीन अब नई चाल चल रहा है। भारत के साथ वह जल युद्ध लड़ने की तैयार में है। चीन के रुख को भांपते हुए अब दिल्ली सरकार उसे इस चाल में भी मात देने की तैयारी में जुट गई है। भारत नहीं चाहता कि वह किसी भी मोर्चे पर चीन से कमजोर साबित हो, ऐसे में उसने अरुणाचल प्रदेश में चीन की नई चाल के खिलाफ घेरेबंदी शुरू कर दी है।

भारत सरकार ने अरुणाचल के सुबानसिरी में चल रहे 11 हजार मेगावाट के हाईड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को फास्टट्रैक पर डाल दिया है। इसके अलावा उसने पहले से तीन स्थापित प्रोजेक्ट के विस्तार का काम भी शुरू कर दिया है।

चीन की नई चाल भारत के साथ जल युद्ध लड़ने की है। वह भारत को सूखे या फिर बाढ़ से नुकसान पहुंचाना चाहता है। इसके लिए चीन अरुणाचल प्रदेश सीमा के पास यारलुंग जैंगबो नदी(ब्रह्मपुत्र) पर 60 हजार मेगावाट का डैम बना रहा है, जिसने भारत की चिंता बढ़ा दी है। अधिकारियों को चिंता है कि चीन इस डैम के जरिए ब्रह्मपुत्र नदी के पानी को डाइवर्ट कर सकता है, या फिर पानी को छोड़कर भारत में

बाढ़ जैसी स्थिति पैदा कर सकता है। अगर ऐसा होता है तो अरुणाचल प्रदेश, असम, समेत कई राज्यों में समस्या उत्पन्न होगी, साथ ही बांग्लादेश पर भी असर पड़ेगा।

चीन को जल युद्ध के मोर्चे पर भी करार जवाब देने के लिए भारत ने कमर कस ली है। अरुणाचल प्रदेश में डैम प्रोजेक्ट के काम को तेज कर दिया गया है, उधर 2000 मेगावाट वाला सुबंसीरी प्रोजेक्ट इस साल के मध्य में तैयार हो जाएगा। इसके आलवा अन्य हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट भी लाइन में हैं। ये प्रोजेक्ट एक साल तक पानी स्टोर कर सकते हैं। अगर चीन डैम के जरिए पानी छोड़ता है, तो उसे रोका भी जा जकता है। बता दें, भारत के लिए ब्रह्मपुत्र नदी काफी अहम है। यह नदी का 30 प्रतिशत ताजे पानी का स्रोत है, तो 40 प्रतिशत बिजली उत्पादन भी इसी से होता है। वहीं इस नदी का 50 फीसदी हिस्सा चीन में पड़ता है, जिस पर वह डैम बना रहा है।

हनीमाधू इंटरनेशनल एयरपोर्ट का शिलान्यास, विदेश मंत्री बोले- भारत-मालदीव संबंधों के लिए बेहद अहम

माले ।

भारत के विदेश मंत्री तीन दिवसीय दौरे पर मालदीव और श्रीलंका के दौरे पर हैं। दौरे के तहत जयशंकर प्रसाद बुधवार को मालदीव पहुंचे। वहां मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलिह के साथ भारतीय विदेश मंत्री एस. जयशंकर हनीमाधू इंटरनेशनल एयरपोर्ट के भूमिपूजन कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान भारतीय विदेश मंत्री ने हनीमाधू इंटरनेशनल एयरपोर्ट पुनर्विकास प्रोजेक्ट को भारत और मालदीव के संबंधों के लिए ऐतिहासिक पड़ाव बताया। कार्यक्रम के दौरान अपने संबोधन में भारतीय विदेश मंत्री ने कहा कि भारत की मालदीव के साथ साझेदारी, एक दूसरे के हितों की पूर्ति और कल्याण की इच्छा पर निर्भर हैं। उन्होंने कहा कि हमारी साझेदारी एक दूसरे की मदद से चुनौतियों का सामना करने के लिए है, जैसा हालिया कोरोना महामारी के दौरान देखने को मिला। आज के मुश्किल भू-राजनैतिक समय में, जब नए गतिरोधों की वजह से दुनिया का हर देश प्रभावित है। ऐसे समय में परस्पर सहयोग और साझेदारी और भी अहम हो गई है।

कार्यक्रम के बाद एक ट्वीट में जयशंकर प्रसाद ने लिखा कि मालदीव में बढ़ती भारतीय पर्यटकों की संख्या से पता चलता है कि दोनों देशों के संबंध

मजबूत हो रहे हैं। मोदी सरकार में अब आधारभूत ढांचे और कनेक्टिविटी को बेहतर करने पर फोकस किया जा रहा है। मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलिह ने कहा कि हनीमाधू इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्रोजेक्ट काफी सुनियोजित तरीके से स्टडी के बाद शुरू किया जा रहा है। देश के माले क्षेत्र से अलग यह एक महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है।

सोलिह ने बताया कि इस प्रोजेक्ट की फंडिंग 2.1 बिलियन एमवीआर एक्जिम बैंक ऑफ इंडिया ने की है। साथ ही इस प्रोजेक्ट को पूरा करने की जिम्मेदारी भारत की कंपनी जेएमसी को दी गई है। राष्ट्रपति सोलिह ने बताया कि इस परियोजना के पूरा होने से मालदीव के उत्तरी क्षेत्र में भी आर्थिक प्रगति देखने को मिलेगी। इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पुनर्विकास से इस इलाके में गेस्ट हाउस, होटल और पर्यटन संबंधी सुविधाओं का विकास होगा। इससे लोगों को रोजगार मिलेगा और यह क्षेत्र आर्थिक केंद्र के रूप में उभरेगा।

पाकिस्तान को मिला अमेरिका का साथ

यूएसए ने कहा- जितनी हो सकेगी, उतनी मदद करेंगे

वॉशिंगटन ।

गंभीर आर्थिक संकट में फंसे पाकिस्तान को अपने पुराने सहयोगी अमेरिका का समर्थन मिला है। पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार तेजी से कम हो रहा है। इस बीच अमेरिकी सरकार के प्रवक्ता नेड प्राइस ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि अमेरिका चाहता है कि पाकिस्तान आर्थिक रूप से निर्भर बने। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार घटकर 4.3 बिलियन डॉलर हो गया है, जिससे सिर्फ तीन हफ्ते का निर्यात किया जा सकेगा। ऐसे में अगर पाकिस्तान को जल्द मदद नहीं मिली तो उसकी अर्थव्यवस्था बुरी तरह चरमरा सकती है।

अमेरिकी सरकार के प्रवक्ता नेड प्राइस ने बुधवार को अपनी रोजाना होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि यह (पाकिस्तान का आर्थिक संकट) एक चुनौती है और हमारी भी इस पर नजर

है। पाकिस्तान, आईएमएफ और अंतरराष्ट्रीय आर्थिक संस्थानों के साथ बातचीत कर रहा है। वो बातचीत चल रही हैं और हम भी जहां तक कर सकते हैं वहां तक अपने पाकिस्तानी सहयोगियों की मदद करेंगे लेकिन आखिरकार यह बातचीत पाकिस्तान और अंतरराष्ट्रीय आर्थिक संस्थानों के बीच का मामला है। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान आर्थिक रूप से निर्भर बने। पाकिस्तान को आईएमएफ से मिलने वाली अगली किस्त का इंतजार है जो उसकी परेशानियों को कुछ कम कर सकती है लेकिन आईएमएफ ने अभी अगली किस्त पर रोक लगाई हुई है। इस गतिरोध को खत्म करने के लिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने 6 जनवरी को अंतरराष्ट्रीय मोनेट्री फंड की चीफ क्रिस्टालिना जियोर्जियेवा से बातचीत भी की थी। हालांकि आईएमएफ ने फिलहाल नई किस्त जारी करने पर रोक लगाई हुई है। दरअसल आईएमएफ का कहना है कि पाकिस्तान ने पिछली किस्त जारी करने के समय जो वादा किया था, वह उसे नहीं निभा रहा है। गौरतलब है कि पाकिस्तान में आर्थिक हालात इस कदर बिगड़ चुके हैं कि वहां खाने-पीने की जरूरी चीजों का संकट पैदा हो गया है। आटा, दाल आम आदमी की पहुंच से बाहर होते जा रहे हैं, साथ ही आटे-दाल की कमी भी आम जनता की परेशानी बढ़ा रही है। हाल ही में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने भारत के सामने दोस्ती का हाथ बढ़ाया है। पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान ने भारत के साथ तीन युद्ध लड़े हैं। अब पाकिस्तान ने अपना सबक सीख लिया है। हम दोनों पड़ोसी देश हैं और दोनों को एक दूसरे के साथ रहना है। अब यह हमारे ऊपर है कि हम मिलजुलकर शांति से रहें या फिर लड़ाई झगड़े में समय के सात संसाधनों की भी बर्बादी करें।